



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 12 मार्च, 2025

फाल्गुन 21, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग—2

संख्या 331/ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी०सी० 282-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश (346)-2025  
लखनऊ, 12 मार्च, 2025

अधिसूचना

प०आ०—६०

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2017–18 या 2018–19 या 2019–20 या 2020–21 या 2021–22 या 2022–23 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब फीस की रकम, जो उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर—9 के प्रस्तुत करने की तारीख तक उक्त अधिनियम की धारा—47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस के आधिक्य में है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जिनसे उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर 9 में वार्षिक विवरणी के साथ प्ररूप जीएसटीआर—9ग में सुलह विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित था लेकिन प्ररूप जीएसटीआर—9 में उक्त विवरणी के साथ उसे प्रस्तुत करने में असफल रहे और जो उक्त विवरण तत्पश्चात 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले प्ररूप जीएसटीआर—9ग में प्रस्तुत करें, का एतद्वारा अधित्यजन करते हैं:

परंतु यह कि उक्त वित्तीय वर्षों के लिए प्ररूप जीएसटीआर—9ग को देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में पहले से संदर्भ विलंब फीस का कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

आज्ञा से,  
एम० देवराज,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 331 / XI-2-25-9(47)-17-T.C.282-U.P.Act-1-2017-Order(346)-2025, dated March 12, 2025 :

No. 331 / XI-2-25-9(47)-17-T.C.282-U.P.Act-1-2017-Order(346)-2025

*Dated Lucknow, March 12, 2025*

IN exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee referred to in section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act, for the financial years 2017-18 or 2018-19 or 2019-20 or 2020-21 or 2021-22 or 2022-23, which is in excess of the late fee payable under section 47 of the said Act upto the date of furnishing of FORM GSTR-9 for the said financial year, for the class of registered persons, who were required to furnish reconciliation statement in FORM GSTR-9C along with the annual return in FORM GSTR-9 for the said financial year but failed to furnish the same along with the said return in FORM GSTR-9, and furnish the said statement in FORM GSTR-9C, subsequently on or before the 31st March, 2025:

Provided that no refund of late fee already paid in respect of delayed furnishing of FORM GSTR-9C for the said financial years shall be available.

By order,  
M. DEVARAJ,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०य०पी०—ए०पी० 566 राजपत्र—2025—(1533)—599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।  
पी०एस०य०पी०—ए०पी० 30 सां राज्य कर—2025—(1534)—500+500=1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।